महत्वपूर्ण एवं खास

मुआवजा देने में किया पक्षपात, प्रभावितों का आन्दोलन जारी

कोरबा। गेवरा पेंड्रारोड रेल कॉरीडोर से प्रभावित भू.विस्थापित अपनी मांगो को लेकर डटे हुए है। दीपका के कृष्णा नगर में आंदोलन किया जा रहा है। रेल प्रबंधन मुआवजा भुगतान को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहा है। भू-विस्थापितों ने रेल पटरी पर खड़े होकर सांकेतिक प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांगो को पूरा नहीं किया गया तो उन्हें रेल रोकना पड़ेगा। रेल कारीडोर के लिए प्रबंधन को अपनी कीमती जमीन देने वाले दीपका स्थित कृष्णा नगर के 16 परिवार आज काफी पछता रहै है। रेल प्रबंधन द्वारा उन्हें पूरा मुआवजा नहीं दिया जा रहा है जिससे आक्रोशित होकर उनके द्वारा पिछले कई दिन से प्रदर्शन किया जा रहा है बावजूद इसके उनकी मांगो को पूरा करने को लेकर किसी तरह का ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कई जतन करने के बाद भी जब बात नहीं बनी तब आंदोलनकारी रेल पटरी के बीच आ गए और हाथों में तख्मी लेकर सांकेतिक रुप से प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कर दिया है,कि अगर उनकी मांगो को जल्द पूरा नहीं किया गया तो वे रेल रोकेंगे। उनकी जमीन का मुआजवा 25 लाख रुपए आ रहा है लेकिन रेल प्रबंधन 18 लाख रुपए देकर अपना पल्ला झाड़ चुका है। प्रदर्शनकारी भी मानने को तैयार नहीं है और कहा है, कि जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिल जाता तब तक वे आंदोलन पर डटे रहेंगे।

नक्सल दंपत्ति सहित चार ने किया समर्पण

सुकमा (आरएनएस)। सुकमा में पुना नर्कोम अभियान का बड़ा असर देखने को मिला है। इस अभियान के तहत चार नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिसमे एक महिला नक्सली भी शामिल है। आत्म समर्पण किए सभी नक्सली कोंटा के भेज्जी इलाके में सक्रिय थे। एसपी सुनील शर्मा के समक्ष आत्म समर्पण किया गया। इन्हें अब पुनर्वास नीति का लाभ दिया जाएगा। नक्सल मोर्चे पर सुरक्षा बल आपरेशन के साथ-साथ सामाजिक सरोकार पर भी काम कर रहा है। जिले में संचालित पुना नर्कोम अभियान के तहत नक्सली मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं। पुलिस अधीक्षक के समक्ष नक्सली दंपत्ति समेत चार नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर • मुख्यधारा से जुड़ कर काम करने की इच्छा जताई है। वहीं इन चारों को प्रोत्साहन राशि दी गई और पुनर्वास नीति का • लाभ देने की बात कही।

पैसेंजर व नाईट एक्सप्रेस यात्री ट्रेन 26 तक किरंदूल नहीं जायेगी

जगदलपुर (आरएनएस)। नक्सलियों ने 25 अप्रैल को बंद का आह्वान किया है, ऐसे में ईको रेलवे ने ऐहतियात बरतते हुए यात्री ट्रेनों का परिचालन दक्षिण बस्तर तक नहीं करने का निर्णय लिया है। किरंदुल तक जाने वाली यात्री ट्रेनों में 18551 और 18552 किरंदुल-विशाखापट्टनम पैसेंजर के साथ ही 18513-18514 किरंदुल-विशाखापट्टनम नाईट एक्सप्रेस को जगदलपुर में ही रोके जाने के निर्देश दिए गए हैं। रेलवे सूत्रों के अनुसार किरंदुल-विशाखापट्टनम पैसेंजर एवं किरंदुल-विशाखापट्टनम नाईट एक्सप्रेस 26 अप्रेल तक किरंदूल से जगदलपुर के बीच नही चलेगी। वहीं दक्षिण बस्तर के दंतेवाड़ा और किरंदुल रेल सेक्शन में माल गाडिय़ों के परिचालन के लिए जो आदेश जारी किया गया है, उसके मुताबिक रात 08 से 9:30 बजे के बीच जगदलपुर के रास्ते बैलाडीला जाने वाली माल गाडिय़ों को दंतेवाड़ा में और बैलाडीला से निकलने वाली माल गाडिय़ों को किरंदुल बचेली में रोका जाएगा। रात 9:30 बजे के बाद गुड्स ट्रेनों का आवागमन सामान्य दिनो की तरह ही रहेगा। रेलवे के सीनियर एसएमआर एमआर नायक ने बताया कि ईको रेलवे मंडल मुख्यालय से जो आदेश प्राप्त हुआ है, उसी के आधार पर यात्री ट्रेनों एवं माल गाडिय़ों का परिचालन किया जाएगा।

धमधा की पहचान देश में उद्यानिकी फसलों से, मंडी के आरंभ हो जाने से अब किसानों के लिए बढ़ेंगे आर्थिक अवसर

❐ 11 करोड़ रुपये की लागत से बने मंडी के उद्घाटन अवसर पर अपने संबोधन में कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने

❐ किसानों के साथ किया लंच, उद्यानिकी फसलों की बेहतरी के लिए किए जाने वाले उपायों पर की बातचीत

रायपुर (आरएनएस)। 11 करोड़ रुपये की लागत से बने मंडी के उद्घाटन अवसर पर अपने संबोधन में कहा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज धमधा में 55 करोड़ रुपये की लागत से धमधा ब्लॉक में विभिन्न कार्यों का लोकार्पण एवं भूमिपूजन एवं सामग्री वितरण किया। इस मौके पर उन्होंने 11 करोड़ रुपये की लागत से बने सब्जी एवं फल मंडी का लोकार्पण किया। साथ ही 1 करोड़ 75 लाख रुपये की लागत से बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी भवन का लोकार्पण भी किया। साथ ही जलसंसाधन विभाग की 18 करोड़ रुपये की योजनाओं का लोकार्पण तथा पीएचई विभाग की 15 करोड़ रुपये की योजनाओं का भूमिपूजन भी किया।

किसानों के साथ किया लंच, उद्यानिकी फसलों की बेहतरी के लिए किए जाने वाले उपायों पर की बातचीत

उन्होंने इस अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि धमधा की पहचान छह आगर, छह कोरी तालाब की है। इसकी ऐतिहासिक पहचान हमेशा से रही है। अब इसकी पहचान टमाटर के उत्पादन और उद्यानिकी फसलों से भी बनी है। धमधा के किसानों ने देश और देश के बाहर बांग्लादेश और पाकिस्तान में भी सप्लाई की है। किसानों की यह उपलब्धि शानदार रही है। इसके पीछे कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे की मेहनत भी है। उन्होंने मंडी की जो योजना बनाई, उसे हमने स्वीकृत किया। उन्होंने बहुत शीघ्रता से और अच्छे से इसे मूर्त रूप दिया है। इस मंडी के बन जाने से किसानों को फसल को उचित मूल्य मिल सकेगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने धमधा के स्वास्थ्य केंद्र को 50 बिस्तर तक अपडेट करने की घोषणा की। साथ ही उन्होंने पीएससी, सेना भर्ती एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में की कोचिंग भी धमधा में आरंभ करने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने एक करोड़ की लागत से स्टेडियम की घोषणा भी की। धमधा महाविद्यालय में ऑडिटोरियम के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा भी की। इसके साथ ही उन्होंने धमधा में तालाबों के सौंदर्यीकरण की घोषणा भी की। उन्होंने बंधुआ तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए एक करोड़ रुपए की राशि की घोषणा की। साथ ही 1 करोड़ रुपए के वितरण कार्य- इस मौके पर मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों को सामग्री वितरण भी किए। उन्होंने 50 किसानों को ट्रैक्टर वितरण किया। मत्स्य कृषकों को भी नाव, जाल, मत्स्य आहार आदि वितरित किए। इसके साथ ही उन्होंने समाज कल्याण विभाग के हितग्राहियों को भी बाइक प्रदान की। इस मौके पर जिला मंडी बोर्ड अध्यक्ष अश्विनी साहू ने भी अपना संबोधन दिया।

धमधा में सामुदायिक भवन के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा भी की। अपने उद्बोधन में मुख्यमंत्री ने कहा कि धमधा के विकास के लिए हर संभव कदम सरकार ने उठाए हैं। इसके साथ ही निरंतर विकास कार्य किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब धमधा की पहचान उद्यानिकी फसलों से है। उद्यानिकी फसलों के विकास के लिए मंडी बनाई गई है, इसके साथ ही किसानों को हर संभव मदद करने एवं नवाचार अपनाने के लिए की योजनाएं बनाई गई है। इस मौके पर अपने संबोधन में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि धमधा के किसानों के लिए मंडी का आरंभ होना बहुत शुभ संकेत है, मंडी के आरंभ होने के पश्चात अब यहां के किसानों को देशभर का मार्केट मिल सकेगा। पहले भी हमारे किसान हैदराबाद से इलाहाबाद तक अपने उत्पाद पहुंचाते रहे हैं, अब मंडी के माध्यम से उन्हें उचित दाम मिल पाएगा। यह मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की सरकार की बहुत अच्छी भेंट धमधा ब्लाक को है। उन्होंने कहा कि मोती नाला तथा रौंदा जलाशय से सिंचाई की व्यवस्था और बेहतर हो सकेगी। इन 3 सालों में धमधा में सिंचाई का दायरा बढ़ाने के लिए बड़े कार्य किए गए हैं।

हितग्राहियों को सामग्री वितरण भी किए-

छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग को मिला सीएसआई-एसआईजी का ई-गवर्नेंस अवार्ड

❐ स्कूली बच्चों के आंकलन एवं अभ्यास की टेली-प्रेक्टीज को रिकग्निशन केटेगरी में मिला अवार्ड

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग कां सीएसआई-एसआईजी (कम्प्यूटर सोसायटी ऑफ इंडिया स्पेशल इंट्रेस्ट ग्रुप) के ई-गवर्नेंस अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य को यह अवार्ड स्कूली बच्चों के आंकलन एवं अभ्यास कार्य को आसान बनाने के लिए लागू टेली-प्रेक्टीज के लिए रिकग्निशन केटेगरी में प्रदाय किया गया है। प्रयागराज स्थित मोती लाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आज आयोजित 19वां सीएसआई-एसआईजी ई-गवर्नेंस अवार्ड को छत्तीसगढ़ की ओर से शिक्षा विभाग के डॉ. एम. सुधीश एवं एनआईसी की ओर से वरिष्ठ तकनीकी संचालक सोम शेखर एवं वरिष्ठ वैज्ञानिक ललिता वर्मा ने प्राप्त किया। गौरतलब है कि शिक्षा विभाग में आंकलन एवं अभ्यास को आसान बनाने के लिए टेली-प्रेक्टीज कार्यक्रम प्रमुख सचिव स्कूल शिक्षा डॉ. आलोक शुक्ला एवं सचिव डॉ. कमलप्रीत सिंह के मार्गदर्शन में संचालित किया जा रहा है।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा बच्चों के आकलन एवं अभ्यास कार्य को आसान बनाने एवं आकलन की प्रक्रियाओं में आमतौर पर होने वाली विसंगतियों को दूर करने राष्ट्रीय सूचना केंद्र (एनआईसी) के सहयोग से टेली-प्रेक्टीज नामक कार्यक्रम लागू किया जा रहा है। इसमें शिक्षकों एवं विद्यार्थियों को टेलीग्राम में एक समूह बनाकर कार्य करना होता है। बच्चों के समक्ष प्रश्न आते-जाते हैं जिनका बिना समय गंवाए बच्चों को जवाब देना होता है। प्रत्येक बच्चे ई-जवाब का अपने आप अलग-अलग वीडियो बन जाता है। इन वीडियो को बाद में शिक्षक देखकर बच्चों का आकलन कर सकते हैं। इसी प्रकार बच्चे अपने उत्तर वाले वीडियो देखकर अगली बार अपनी त्रुटियों को सुधार कर सही उत्तर चनुकर अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं।

टेली-प्रेक्टीज कार्यक्रम पूर्णत: छत्तीसगढ़ में एनआईसी छत्तीसगढ़ के सहयोग से स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उपयोग में लाया जा रहा है। इसमें उपयोग में लाए जाने वाले प्रश्न भी यहाँ के शिक्षक ही तैयार करते हैं। विभिन्न संस्थाओं ने राज्य में प्रचलित टेली-प्रेक्टीज को देखा है और उन्हें बच्चों के अभ्यास एवं शिक्षकों के आंकलन संबंधी कार्यों को आसान करने हेतु उपयोगी पाया है। इसे एनआईसी से उनके वरिष्ठ तकनीकी संचालन सोम शेखर के नेतृत्व में तैयार किया गया है। राज्य में इसकी पायलटिंग समग्र शिक्षा से डॉ. एम. सुधीश के निर्देशन में की गयी है।

पूर्व विधायक बोधराम को दीक्षांत समारोह में मिली डॉटरेट की उपाधि

कोरबा। अटल बिहारी वाजपेई यूनिवर्सिटी बिलासपुर के तीसरे दीक्षांत समारोह में 7 बार विधायक रह चुके बोधराम कंवर को डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी (विद्या वाचस्पति) मानद उपाधि दी है। समारोह में राज्यपाल अनुसूइया उइके और उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने सम्मान पत्र सौंपा। बोधराम कंवर ने एमएससी में गोल्ड मेडलिस्ट है। उन्होंने कोरबा जिला के पाली विकासखंड अंतर्गत हरदी बाजार में आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए ग्राम भारती विद्यापीठ महाविद्यालय (कॉलेज) की स्थापना की। अब कॉलेज का संचालन राज्य सरकार कर रही है।

कथावाचिका प्रेमलता शुक्ला को मिला स्वर्णमंडित पदक

कोरबा। कोरबा की प्रसिद्ध भागवत कथावाचिका प्रेमलता शुक्ला को एम.ए.संस्कृत की प्रावीण्य सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर उन्हें स्वर्णमंडित पदक से सम्मानित किया गया है, शुक्ला की उक्त महत्वपूर्ण उपलब्धि पर निगम परिवार के सदस्य एवं उनके शुभचिंतक गौरान्वित महसूस कर रहे हैं।

कोरबा की प्रसिद्ध भागवत कथावाचिका प्रेमलता शुक्ला नगर पालिक निगम कोरबा के टी.पी.नगर जोन के जोन कमिश्नर अखिलेश्वर प्रसाद शुक्ला की धर्मपत्नी है। अटल बिहारी बाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर द्वारा वर्ष 2021 में आयोजित एम.ए.संस्कृत अंतिम वर्ष की परीक्षा उन्होने प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की तथा विश्वविद्यालय की प्रावीण्य सूची में पहला स्थान प्राप्त किया। शुक्ला की इस महत्वपूर्ण उपलब्धि के लिए विश्वविद्यालय द्वारा उन्हें स्वर्णमंडित पदक से सम्मानित किया गया है। प्रेमलता शुक्ला भारतीय संस्कृति एवं अध्यात्म में गहरी रूचि रखती हैं, वे काफी समय से विभिन्न धार्मिक आयोजनों में भागवत कथा प्रवचन के माध्यम से श्रद्धालुओं व श्रोताओं को भागवत कथा का गूढ़-ज्ञान व धर्म लाभ प्रदान कर रही हैं। शुक्ला को स्वर्णमंडित पदक से सम्मानित किए जाने एवं उनके द्वारा अर्जित इस बड़ी उपलब्धि के लिए निगम के अधिकारी कर्मचारियों एवं उनके शुभचिंतकों द्वारा लगातार बधाई व शुभकामनाएं दी जा रही हैं।

बीएनआई एवं इनोवेटीव इवेन्ट्स एंड एक्जीबिटर्स कंपनी 30 सितंबर से दो अक्टूबर के मध्य एक्सपो का करेगी आयोजन

❐ देश भर के आर्किटेक्ट इंजीनियर एवं बड़ी कंपनियां होंगी शामिल

रायपुर (आरएनएस)। नवोदित राज्य छग को बने 22 साल होने को है। भारत के अन्य प्रदेशों की तरह नई टेक्नालॉजी से युक्त मकान का निर्माण एवं उससे संबद्ध इकाईयों को एकजुट करने के उद्देश्य से 30 सितंबर से दो अक्टूबर के मध्य हॉकी स्टेडियम साइंस कालेज मैदान में इंडस्ट्रीयल एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है। उक्त आयोजन की जानकारी बीएनआई छग एवं इनोवेटीव इवेंट्स एंड एक्जीबिटर्स के एमडी मनप्रीत सिंह आनंद ने प्रेस क्लब रायपुर में आयोजित पत्रकारवार्ता में दी।

पत्रकारवार्ता में आईआईए छग आईआईडी रायपुर द्वारा उक्त आयोजन को समर्थन दिया जा रहा है। उक्त दोनों संस्थान इंटीरियर डेकोरेटिंग एवं आर्किटेक्ट इंजीनियरिंग के जुड़े हुए हैं। पत्रकारवार्ता में बीएनआई रायपुर के ईडी राजेश बेसिया आईआईए छग चेप्टर के अध्यक्ष राज प्रजापति, वाइस प्रेसीडेंट रवि जग्गी, आईआईए रायपुर सेंटर के अध्यक्ष रवि चौहान, सेकेटरी रिरिदुल शर्मा आईआईडी रायपुर चेयरपरसन शिल्पी सोनार ने संयुक्त रूप से बताया कि रायपुर एवं प्रदेश में मध्यम वर्गीय परिवार एक बंगला बने न्यारा का सपना देखता है। उसके उस सपने को साकार करने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है जिसके जरिए आर्किटेक्ट इंजीनियर इंटीरियर डेकोरेटर की सलाह पर उसे एक मजबूत मकान मिल सके। उन्होंने बताया कि भारत के प्रमुख शहर मुंबई, अहमदाबाद, दिल्ली, हैदराबाद, बैग्लोर सहित मेट्रोपोलिटन शहरों से आने वाले विभिन्न कंपनियों के प्रतिनिधि इंजीनियर आदि बड़े शहरों को बनने वाले शानदार मकानों को खूबसूरती से रायपुर एवं प्रदेश में बनाये जाने की मंशा को लेकर रायपुर आ रहे है। पत्रकारवार्ता में चेंबर ऑफ छग के वरिष्ठ अध्यक्ष रहे सरदार मनमोहन सिंह सैलानी ने पत्रकारवार्ता में बताया कि हर व्यक्ति का जीवन में एक सपना होता है कि उसका परिवार खूबसूरत मकान में रहकर अपनी जिंदगी के खुशनुमा पलों को गुजारे उसकी इसी अभिलाषा को पूर्ण करना उक्त आयोजन का मुख्य उद्देश्य है।

सरकार तुंहर द्वार कार्यक्रम में किसान बंधन सिंह को मिला नया किसान किताब

❐ राजस्व और भूमि संबंधी कार्यों में अब होगी आसानी

कोरबा। कलेक्टर रानू साहू की पहल पर लोगो के विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निराकरण कर एक ही जगह में शिविर के माध्यम से सेवाएं प्रदान करने के लिए आयोजित किये जा रहे सरकार तुंहर द्वार कार्यक्रम के तहत् किसान बंधन सिंह को नया किसान किताब मिल गया। नया किसान पुस्तिका मिल जाने से अब उन्हे खाद-बीज, कृषि लोन एवं समर्थन मूल्य धान बेचने के लिए जरूरी पंजीयन में आसानी होगी। विकासखण्ड कटघोरा के ग्राम दर्री निवासी बंधन सिंह का किसान किताब गुम गया था। सरकार तुंहर द्वार कार्यक्रम के तहत् शिविर के पहले गांव गांव मे सर्वे कर लोगो की समस्याओं की जानकारी ली जा रही थी। इसी दौरान किसान बंधन सिंह ने सर्वे टीम को किसान किताब गुमने की बात से अवगत कराया। राजस्व विभाग के कर्मचारियों द्वारा किसान सिंह से नई किसान किताब बनाने के लिए आवेदन लिए गये। आवेदन लेने के पश्चात् किसान बंधन सिंह का नया किसान किताब बनाया गया। आज कटघोरा विकासखण्ड के भिलाईबाजार में आयोजित सरकार तुंहर द्वार कार्यक्रम में उन्हे नया किसान किताब दे दिया गया। कम समय और बिना कार्यालयो के चक्कर काटे किसान किताब मिल जाने से किसान बंधन सिंह खुश होकर जिला प्रशासन का आभार व्यक्त किया।

किसान सिंह को नया किसान किताब मिल जाने से बैंक और भूमि संबंधी अन्य राजस्व मामलो में भी सहायक होगी। किसान किताब के माध्यम से किसान क्रेडिट कार्ड बनवाकर ब्याज मुक्त कृषि ऋण आदि की सुविधा मिलेगी। किसान किताब में किसान के नाम से भूमि के रकबे और लगान संबंधी जानकारी अंकित रहती है। किसान किताब जमीन की खरीदी बिक्री के समय भी आवश्यक दस्तावेजो के रूप में शामिल रहता है। किसान बंधन सिंह को शिविर स्थल मे किसान किताब मिल जाने से पटवारी और तहसीलदार कार्यालय जाने की जरूरत नही पडी। सिंह को आसानी से और एक ही जगह मे शिविर के माध्यम से किसान किताब प्राप्त हो गया।

रफ्तार से दौड़ रही मालगाड़ियां, सवारी गाड़ियों का हाल बुरा

❐ रेल सुविधा की कमी से हर कोई परेशान, 1800 करोड़ का राजस्व मिलता है कोरबा से

कोरबा। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का कोरबा के साथ सौतेला व्यवहार समाप्त होने का नाम नहीं ले रहा है। यात्री सुविधाओं को लेकर बड़े-बड़े दावे जरूर किये जा रहे है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल अलग है। कोरबा-बिलासपुर रेल सेक्शन पर पूरी रफ्तार से मालगाडिय़ां दौड़ रही है लेकिन सवारी गाडिय़ों का हाल बुरा है। वर्तमान में सीमित गाडिय़ों की लेटलतीफी लोगों के लिए सिरदर्द बन गई है। औद्योगिक जिले कोरबा में रेल सुविधाओं के विस्तार को लेकर काफी समय से मांग की जा रही है लेकिन आश्वासन के अलावा नतीजे देने पर अधिकारी गंभीरता नहीं दिखा रहे हैं। खबर के अनुसार हर वर्ष रेलवे को कोरबा से 1800 की आमदनी होती है पूर्व की तुलना में वर्तमान में पांच गाडिय़ां ही संचालित की जा रही है। इनमें सुबह 6.40 बजे कोरबा से रायपुर के लिए मेमु की सुविधा उपल ध है। एक मात्र साप्ताहिक नियमित ट्रेन छत्तीसगढ़ एक्सप्रेस 11.40 पर सेवा दे रही है। सुबह के समय हसदेव एक्सप्रेस चलायी जा रही है, केवल 4 दिन। सप्ताह में दो दिन यशवंतपुर की सुविधा मिली हुई है। दोपहर बाद 4.10 बजे कोरबा से विशाखापट्नम का संचालन हो रहा है और अंतिम गाड़ी 6 बजे कोरबा से ईतवारी नागपुर के लिए उपलब्ध है। काफी लंबे समय से इसी गाड़ी का रिकार्ड सबसे ज्यादा खराब है। स्पष्ट धारणा बन चुकी है कि यह कब आयेगी और कोरबा से कब छुटेगी, इसे रेलवे के अधिकारी भी सही तरीके से नहीं जानते।

कोरबा और गेवरा रोड से चलने वाली 4 गाडिय़ां बंद पड़ी हैं। इनमें हसदेव को भी शामिल किया गया है। पूर्व में इसकी सेवाएं सप्ताह में सभी दिन मिल रही थी, जिसे सीमित कर दिया गया है। इसके अलावा सुबह 8.15 की पैसेंजर दोपहर की मेमु और शाम को रवाना होने वाली एक अन्य मेमु भी ठप्प है। इनके कारण कोरबा और बिलासपुर -रायपुर की दिशा में आना-जाना करने वाले ये लोग परेशानी झेल रहे हैं। अलग-अलग स्तर पर बंद पड़ी इन रेलगाडिय़ों को चालू करने की मांग की जाती रही है। यह मामला दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के चेयरमेन से लेकर डीआरएम और रेल मंत्री तक जा पहुंचा है। इन सबके बावूजद कोरबा के हित की अनदेखी की गई। सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वर्तमान में केवल 5 ट्रेनों का संचालन कोरबा से हो रहा है। इस पर भी दिक्कत इस बात की है कि सवारी गाडिय़ों की आवाजाही के दौरान बड़ी संख्या में कोयला गाडिय़ों को दौड़ाया जा रहा है। ऐसे में एक तो टाईमिंग गड़बड़ा गई और यात्री गाडिय़ों को डेस्टीनेशन पाईंट तक पहुंचने में अनावश्यक विलंब हो रहा है। संबंधित गाडिय़ों में सफर करने वाला वर्ग जब देर से अपनी जगह पहुंचता है तो उसके निर्धारित कार्यों में व्यवधान होता है। कई मौकों पर लोग अवसर भी खो देते हैं।

रेल संघर्ष समिति के अलावा अलग-अलग स्तर पर लोगों के द्वारा यात्री ट्रेनों से जुड़ी समस्या को लेकर कोशिश की जा रही है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुरे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address :: Behind Stadium Near Career School, Raigarh, C.G. Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU